

लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 2322
21 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्रों का निर्यात और आयात

2322. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान वस्त्रों से संबंधित निर्यात और आयात का ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल विदेशी एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वस्त्रों के आयात को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) वस्त्र उत्पादों के निर्यात हेतु प्रदान की गई सुविधाओं/सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र निर्यात और आयात का विवरण निम्नानुसार है:
भारत का वस्त्र और अपैरल निर्यात

(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	2019-20	2020-21	2021-22
रेडीमेड गारमेंट	15,488	12,272	16,015
कपास वस्त्र	10,263	11,128	17,166
मानव निर्मित वस्त्र	5,324	4,180	6,294
ऊन और ऊनी वस्त्र	181	109	166
रेशम उत्पाद	72	76	109
हथकरघा उत्पाद	319	223	269
कारपेट	1,373	1,491	1,790
पटसन उत्पाद	357	397	537
हस्तशिल्प	1,798	1,708	2,088
हस्तशिल्प सहित कुल टीएंडए (राउंडेड ऑफ)	35,177	31,585	44,435

स्रोत: डीजीसीआईएस अनंतिम डेटा

भारत का वस्त्र और अपैरल आयात

(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	2019-20	2020-21	2021-22 (पी)
रेडीमेड गारमेंट	1,144	881	1,265
कपास वस्त्र	2,759	1,527	2,143
मानव निर्मित वस्त्र	2,682	2,334	3,433
ऊन और ऊनी वस्त्र	332	200	320
रेशम उत्पाद	210	99	148
हथकरघा उत्पाद	10	6	2
कारपेट	118	72	100
पटसन उत्पाद	242	176	248
हस्तशिल्प	764	577	534
हस्तशिल्प सहित कुल टीएंडए (राउंडेड ऑफ)	8,262	5,873	8,193

स्रोत: डीजीसीआईएस अनंतिम डेटा

(ख) और (ग): सरकार, देश में विशेष रूप से वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र), समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना), सिल्क समग्र, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना आदि विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, सरकार वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के माध्यम से देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में संपन्न समझौता; और विभिन्न व्यापारिक भागीदारों के साथ 6 तरजीही व्यापार समझौते शामिल हैं। वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य एवं केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट को जारी रखा है। इसके अलावा, अन्य वस्त्र उत्पाद जो आरओएससीटीएल के तहत शामिल नहीं किए गए हैं, वे अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत आते हैं।

सरकार व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भाग लेने के लिए वस्त्र और अपैरल निर्यात को बढ़ावा देने में लगे विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
